रविवारीय

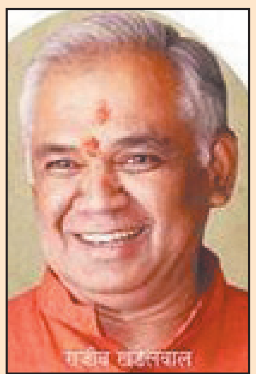

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

सर मतलब सम्मान या.....? देश का हर पढ़ा-लिखा वर्ग—चाहे वह स्कूल, कॉलेज या उच्च शिक्षा से जुड़ा हो—सर को जीवन भर सम्मान देता है. माता-पिता के बाद, शिक्षा देने वाला गुरु ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, जिसे हम सिर झुकाकर ''सर कहकर संबोधित करते हैं. भारतीय परंपरा में गुरु को ''परब्रह्म का दर्जा मिला है—जीवन की दिशा और परलोक की दशा तय करने वाला तत्वज्ञानी. गुरु बिना ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान जीवन अधूरा है. गुरुकुल परंपरा सहित वर्तमान परिवेश में भी वरिष्ठ छात्रों को भी आजीवन सर कहकर ही पुकारा जाता है. लेकिन इन दिनों देश में जिस सर की चर्चा है, वह सम्मान के बजाय विवाद और छीछालेदर का कारण बन गई है.

सर शब्द की इतनी बेइज्जती कभी हुई है क्या?

विशेष गहन पुनरावलोकन (सर) कानूनी बाध्यता बिल्कुल नहीं- निर्वाचन आयोग ने अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के अधीन प्राप्त पुनरावलोकन के अधिकार के तहत, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सटीक व पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने हेतु 24 जून 2025 से ''सर SIR, एसआइआर, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन अर्थात विशेष गहन पुनरावलोकन की कार्रवाई शुरू की है. बिहार में सर की कारवाई इसके पूर्व वर्ष 2003-04 में की गई थी. यद्यपि उच्चतम न्यायालय में चल रही बहस में एक-दो याचिकाकर्ता ने भी चुनौतीपूर्वक सर की कार्रवाई देश में प्रथम बार होना बतलाई.

गौरतलब है कि जनवरी 2025 में विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन पहले ही पूरा हो चुका था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना था, जो एक नियमित प्रक्रिया है. कानूनी रूप से इस समय या कदापि सर की आवश्यकता नहीं थी, परंतु निर्वाचन आयोग ने अपनी तथाकथित निष्पक्ष छवि को मजबूत करने के उद्देश्य से निहित, इनबिल्ट सम्मान की भावना से सर की कार्रवाई शुरू की.

विवाद और सवाल! जवाब?- कहा जाता है कि भाग्य दो कदम आगे चलता है, दुर्भाग्यवश प्रथम ग्रास मक्षिका पात की युक्ति को चरितार्थ करते हुए दुर्भाग्य से, शुरुआत से ही सर विवादों में घिर गया है. सर मुंडाते ही ओले गिरे. सोशल मीडिया, खासकर अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्टिंग ने इसे विष घुला स्वर्ण कलश की संज्ञा दी. राहुल गांधी ने जनता को आगाह करते हुए कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तथाकथित साक्ष्यों के साथ रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत कर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को पाँच श्रेणियों में सूचीबद्ध कर आयोग से जवाब/ स्पष्टीकरण माँगा. तत्पश्चात 300 सांसदों का संसद से आयोग की ओर मार्च और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई ने मामले को और तूल दे दिया.

निष्पक्षता से सर की कार्रवाई की जरूरत- भारतीय परंपरा में सर (सिर) झुकाना सम्मान है, लेकिन सर (गुरु) को झुकाना नहीं. चुनाव आयोग पर यह आरोप है कि उसने आरोपों का निराकरण करने के बजाय उलटे ''बे-सिर-पैर के बयान देकर सर को इतना शर्मिंदा क्यों कर रहा है, जिससे सर का मान घटा. इसलिए हम चुनाव आयोग से यही अनुरोध कर सकते हैं कि वह आरूणी और एकलव्य की गुरु भक्ति के परंपरा वाले इस देश में सर की ऐसी की तैसी न करें. आयोग को चाहिए कि सर के मूल उद्देश्य—निष्पक्ष मतदाता सूची—को ईमानदारी से अक्षरश: धरातल पर उतारें.

मैं आपका गुलाम. सर का एक अर्थ गुलामी भी होता है, जो अंग्रेजों ने दिया है. क्राउन की वफादारी में यह सम्मान सर की उपाधि दी जाती थी. यह संभव है, शायद चुनाव आयोग ने सर के इस गूढ़ अर्थ को लेकर कड़ा जवाब देने के लिए सर की इस तरह की कार्रवाई की हो?

हंडिया में एक चावल देखा जाता है- चुनाव आयोग द्वारा त्रुटिहीन मतदाता सूची के उद्देश्य को लेकर व्यापक पैमाने पर सर की कार्रवाई की जा रही है, जहां प्रत्येक मतदाता को ''गणना फॉर्म '' अनिवार्य रूप से भरकर स्थानीय ''बीएलओ को देना है. वहीं ''बीएलओ का भी यही कार्य है कि, वे घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता से फार्म भरवायें. तब बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के मतदाता सूची में दो बार नाम कैसे आ जाता है? प्रश्न यह है? विजय सिन्हा का इस संबंध में स्पष्टीकरण की मैंने पहले अप्रैल 2024 में और अभी सर की कार्रवाई के बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित होने के पश्चात, 5 अगस्त को फिर से आवेदन एक जगह से नाम काटने के लिए दिया है, स्वयं को तो निर्दोष सिद्ध करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं. विपरीत इसके, विजय सिन्हा का स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को ही कटघरे में डालता है, वह इसलिए कि वे यह नहीं कह रहे हैं कि मैंने दो गणना फॉर्म भरे हैं. विजय सिन्हा कोई सामान्य आदमी नहीं है, जिनको लेकर कोई लिपिकीय त्रुटि दो बार नाम आने की हो जाए? इसी प्रकार क्या राहुल गांधी की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेव पुरा विधानसभा क्षेत्र की अपनी रिसर्च के आधार पर 1,00,250 वोटों की तथाकथित चोरी के आरोप को भी हंडिया में एक चावल की दृष्टि से देखा जाए? यदि आरोप गलत है तो, चुनाव आयोग राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं दायर करते? जिसके राहुल गांधी आदि हो चुके हैं. जिस प्रकार भारत-चीन सीमा पर कुछ हजार वर्ग फुट जमीन को लेकर राहुल के चीन के कब्जे के आरोप को लेकर मानहानि का मुकदमा उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, जहां हाल में ही राहुल की सच्चे भारतीय होने पर माननीय न्यायाधिपति ने प्रश्न चिन्ह लगाया था?

भविष्य के संकेत ठीक नहीं?

आयोग ने ''सर मामले में उच्चतम न्यायालय के सुझावों को भी गंभीरता से नहीं अपनाया, जिससे सरकार, विपक्ष और आयोग—तीनों के बीच संवाद के रास्ते लगभग बंद होकर कहानी कहीं हम निर्वाचित निरंकुशता (इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी) की ओर तो नहीं जा रहे हैं? डर यह है कि कहीं ''सर का अंजाम नोट बंदी की तरह विवादित और बेनतीजा होकर एक नन फाइनेंशियल स्कैम न हो जाए?

बीएलओ पर कम समय में लक्ष्य पूरा करने का दबाव- मतलब साफ है कि बीएलओ ने तय कम समय सीमा में उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त मतदाताओं का निरीक्षण फॉर्म भरवाने के चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों के दबाव के चलते लक्षित उद्देश्य की पूर्ति हेतु निरीक्षण फॉर्म कई जगह घर बैठे भर कर अपलोड कर दिये, जैसा की यू -ट्यूबर अजीत अंजुम की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से लेकर सोशल मीडिया बीएलओ की ऐसी कार्रवाइयों के वीडियो से भरा पड़ा है. तब ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा राजनैतिक पार्टियों से ''सार्थक व व्यापक चर्चा किये बिना बिहार में होने वाले आम चुनाव के पूर्व अचानक ''सर का निर्णय लेने पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है. सर की कवायद में लगभग 1500 से 2000 करोड़ रूपया खर्च होने का अनुमान है. बावजूद इसके मतदाता सूची की पुरानी कमियां, त्रुटियों की पुनर्रावृति, बीएलओ की गलती, अकर्मणता, कार्यप्रणाली व असावधानी के चलते ही असफल सिद्ध हो रही है. इससे विपक्ष को एक आरोप, लगाने के लिए धारदार हथियार मिल जाता है.

सिर्फ केवल 30 सांसदों को अनुमति. आयोग का सही निर्णय- राहुल गांधी की मांग 300 सांसदों से मिलने की बजाय मात्र 30 लोगों को मिलने की अनुमति दी गई. इंडियन गठबंधन के 27 दलों में से 6 दलों का एक भी सांसद नहीं हैं. ऐसे में 21 दलों का प्रतिनिधित्व 21 चुने हुए संसदीय दल के नेताओं द्वारा करना जो स्वयंमेंव 300 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर्याप्त था. बल्कि ज्यादा 9 सांसदों को निमंत्रित करना, निर्वाचन आयोग की वैसे ही मेहरबानी है, जैसे पुराने जमाने में जब हम बाजार में आम खरीदने जाते थे, तब 100 आम पर पांच पुरौनी (पोरन) अतिरिक्त मिलती थी. आयोग का यह निर्णय तार्किक था, परंतु विपक्ष ने इसे भी राजनीतिक मुद्दा बना, मुद्दे की गंभीरता की बलि ले ली.

निष्कर्ष- निर्वाचन आयोग के लिए यह समय अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता सिद्ध करने का है. सर को सम्मान लौटाने का एकमात्र तरीका है—त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाना और जनता को यह भरोसा दिलाना कि ''ये पब्लिक है, सब जानती है कोई खोखला जुमला नहीं. जेपी आंदोलन की उर्वरक भूमि बिहार की ही थी, शायद इस कारण कुछ लोगों की नजर में सांसदों के मार्च-पास्ट से जेपी आंदोलन समान कोई आहट तो नहीं? जेपी आंदोलन से निकली भाजपा, तथाकथित ऐसे किसी भी आंदोलन की आहट को भांपने में सक्षम है.

व्यंग्य

गड्ढों से संवाद

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं

इन दिनों पूरे देश में सड़क पर होने वालों की खूब खबरें चर्चा में हैं. फिर चाहे वे खबरें प्रिंट मीडिया में हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. खबरें तो खबरें हैं. मेरा ऐसा मानना है कि अखबारों की खबरें रद्दी में बिक जाने के बाद भी अजर अमर होतीं हैं. वे भले ही रंग में श्यामल हों, पर ज्यादा दिनों तक असर कारक बनी रहतीं. जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें छोटे पर्दे पर कुछ ही मिनटों में झलक दिखा कर ओझल हो जातीं हैं. श्रोताओं का टीवी की खबरों पर इसलिए कम ध्यान जाता है क्योंकि वह यह तय नहीं कर पाता है कि वह दर्शक है या श्रोता. आंखें एंकर को टकटकी लगाए देखतीं हैं तो,कान काम करना बंद कर देतें हैं. साथ ही दिमाग भी कह देता है ले भाई अब तू एंकर को ही निहार ले. मैं तो चला. न्यूज चैनल्स वालों को सुझाव है कि प्राइम समाचार के समय पुरूष एंकर्स को लगाएं ताकि समाचार ग्राह्य बन सकें. जबकि प्रिंट मीडिया की खबर पर आंखें और दिमाग एक साथ असर करते हैं मुख खबर पढ़ कर सुनाता है और दिमाग में खबर सेव (कैद) हो कर रह जाती हैं. जबकि न्यूज चैनल की न्यूज पल्ले न पड़ने का मुख्य कारण है, ई मीडिया की वह खूबसूरत सजी धजी एंकर . इस पर मेरे दिलो दिमाग में एक फिल्मी गीत की डिस्क चलने लगती है..तेरे चेहरे से नजर नहीं हटतीं..खबरें हम क्या ख़ाक देखें. यही एंकर्स दिन भर के हारे-थके श्रोता सह दर्शक को उत्साह से लबरेज कर देतीं हैं. उस समय श्रीमती जी का पास बैठना भी खटकता है. हम एंकर की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं और श्रीमती जी आंखों में शोले लिए हम को घूर रहीं होतीं है. यह तो हम सब जानते हैं कि हर चीज का सीजन होता है जैसे शादियों का सीजन, स्कूलों में भरती का सीजन, परीक्षा का सीजन, उसी तरह मानसून का सीजन होता है. मानसून सड़कों पर बरसता है तो संसद और विधानसभा में तो नेता बिन मौसम ही बरसते हैं. वे व्यवस्था में गड्ढे ढूंढते हैं और रिपोर्टर सड़कों में गड्ढे . वे सड़कों के गड्ढे ढूंढ-ढूंढ कर जनता को बताते हैं देखो कहां कहां गड्ढे हैं. जनता कहती है जागो सियासी मोहन प्यारों या प्यादों हमारी तरफ भी देखों. इन गड्ढों को पाट दो क्योंकि कल तुम को भी वापस लौट कर यहीं सड़क पर ही आना है. उसी तरह जैसे पंछी उड़ कर वापस अपने घोंसले में आता है. उड़ी सड़क को पंछी, पुनि सड़क पर आवे.

नेता लोग और एक्टिविस्ट, जिन्हें खुद को समाज सेवी कहलाने का शौक है .इन गड्ढों पर पौध रोपण का नाटक कर अपना फोटो खिंचवाने और उन्हें पेपर में छपवाने पर अधिक ध्यान देते हैं. गड्ढों को भरने में उनकी दिलचस्पी नहीं होती. उनकी दिलचस्पी लाइम लाइट में बने रहने की रहती है. उनकी समाज सेवा फोटो छपवाने भर की होती है.

हमने सोचा कि सड़कों पर पैदल और दु-पहिया, चुपहिया वाहनों पर चलने वाले सभी, सडकों के गड्ढों को कोसते नजर आते हैं. किसी को भी गड्ढों और सड़क के दु:ख का पता ही नहीं है कि वे किस हद तक और कहाँ तक घायल हैं. यह सब सोचते हुए हमने तय किया कि चलो हम सड़कों के दु:ख जानने के लिए उनके मन को टटोलें उन के दुखों पर मलहम लगाएं. जब सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ तो हम कुछ गड्ढों के पास जा पहुंचे. हमने उन से कहा भाई जी हम आपका दु:ख जानने आए हैं. हमारी बात सुनकर गड्ढे में भरा पानी हिलने लगा. मानो वह हंस रहा हो. गड्ढे ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा. भाई आप पहले आदमी हैं जो हमारा दु:ख जानने आए हो, वरना तो यहां से गुजरने वाले हमें गालियां देते हुए थकते नहीं हैं. वे जानबूझकर कर अपने भारी भरकम वाहनों के पहिये हम में कूदा कर हमें और भी छलनी करते और पैदल चलने वालों के कपड़ों पर छपाक से पानी उड़ा कर उनका मज़ाक उड़ाते हुए निकलते हैं.

हमने पूछा, अच्छा गड्ढा भाई ये बताओ कि अक्सर तुम बरसात के सीजन में सड़क पर क्यों निकल आते हो. वो बोला भाई हमारा जनक लोकतंत्र है .उन्हीं की वजह से हम, न चाहते हुए भी सरकारी दफ्तर की सेफ में रखीं सुरक्षित फाइलों से निकाल कर सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं. हमारा जन्म सरकारी बाबुओं औरअधिकारियों की लालच की प्रसव पीड़ा से हमारा जन्म सड़कों पर हो जाता है. भ्रूण अवस्था में हम छोटे से होते हैं .फिर वाहनों की ठोकर खा-खा कर लालच की तरह विशाल रूप धारण कर लेते हैं. फिर जब सब कुछ सेट हो जाता है तो हमारे मुंह में गिट्टी, सीमेंट या गर्मा गर्म डामर भर देते हैं. तब गड्ढे की जगह ऊंट की पीठ की तरह कूबड़ निकल आती है. जिस पर से जब वाहन निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊंट की सवारी कर रहे हों.

गड्ढों ने बताया कि हमारा जन्म फाइलों से होता है और निर्वाण भी उन्हीं फाइलों में हो जाता है. हम यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हैं. हम राजघाट पर भी हैं और राजपथ पर भी मौजूद हैं . हम कर्तव्य पथ पर हैं तो जनपथ में भी हमारी पैंठ है. सभी सरकारी फाइलों, गोदामों, निर्माण कार्यों, तालाबों, बांधों में, जल में थल में और नभ में भी हम गड्ढों के रूप में मौजूद हैं. हम अन्याय में भी हैं और न्याय में भी हैं. उन्होंने बताया कि हम गड्ढों, से भी आदमी सीख सकते हैं, लेकिन आदमी सीखता कहाँ है. वो उलटे हम को ही चार उपदेश दे कर मुस्कराते हुए आगे बढ़ जाता है. हम ने पूछा गड्ढा भाई यह बताओ कि आपसे क्या सीखा जा सकता है. वह बोला हम से संभल कर चलना और आंखें खोल कर चलना सीखा जा सकता है. यह सीखा जा सकता है कि जो पहले से ही क्षतविक्षत है उसके जख्मों को और न कुरेदा जाए. हम को बनाने का श्रेय जिन विभाग के बाबुओं अधिकारियोंऔर घटिया माल का इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों को हैं वे यह सीख सकते हैं कि उनकी वजह से कितनी मां की गोद, पत्नि की मांग सुनी होती है और कितने बेटी बेटे असमय ही अनाथ हो जाते हैं.

अमेरिका के टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी ट्रेड ओरिएंटेड नहीं है. साथ ही अमेरिका को जाने वाला एक्सपोर्ट भारत की जीडीपी का मात्र दो प्रतिशत है. इसके अलावा फार्मा और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे बड़े सेक्टर पहले ही टैरिफ से बाहर हैं. अमेरिका भी यह बेहतर रूप से जानता है कि उसे भारत की आवश्यकता है. आज विश्व में कोई भी देश भारत को इग्नोर नहीं कर सकता. भारत की शक्ति का लोहा पूरा विश्व आज मानता है. आज देश की जनता यह कहती है नरेंद्र मोदी देश के लिए वरदान है जो 100 प्रतिशत सही है.

अंकल सैम यह मोदी का देश न झुकता है न डरता है

राकेश शर्मा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट को खरीदे. साथ ही अमेरिका से रक्षा उत्पादन सामग्री भी खरीदे पर देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता में देश का हित पहले है.

भारत की रीढ़ हमारे किसान भाई बंधु हैं जो उत्पाद वह पैदा करते हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है. आज विश्व में हम गेहूं, चावल एवं अन्य कृषि उत्पादन निर्यात कर रहे हैं जो एक हमारी बड़ी ताकत है. अमेरिका लगातार भारत से कह रहा है कि भारत अमेरिका का मिल्क प्रोडक्ट खरीदे जबकि अमेरिका में गायों को चारे में मीट मिलाकर खिलाया जाता है. भारत में अपना दूध उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है और सनातन धर्म को मानने वाले भारतीय अमेरिका का दूध जिसमें गाय को चारे में मीट मिलाकर खिलाया जाता है उस दूध को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे.

अमेरिका को भारत से एक बड़ी तकलीफ यह भी है कि भारत लगातार रसिया से क्र ड ऑयल तेल आयात कर रहा है. रसिया लगातार भारत को सस्ती दर पर क्र ड ऑयल दे रहा है. अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिका से क्र ड ऑयल दोगुने दाम पर खरीदे. भारत ने स्पष्ट कर दिया कि देश की जरूरत और हितों को वह पहली प्राथमिकता रखेगा. इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोखला गए हैं और लगातार टैरिफ की धमकी अमेरिका भारत को दे रहा है. पहले 25 प्रतिशत टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाया और जब देखा भारत उसके सामने नहीं झुक रहा और उसकी शर्तों को नहीं मान रहा तो यही टैरिफ 50 प्रतिशत कर दिया. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत के किसान उनकी पहली प्राथमिकता हैं और किसानों के हित में देश हमेशा खड़ा रहेगा. भारत का हर नागरिक अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है और उन्हें अमेरिका के प्रति अति गुस्सा है. शायद अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप यह नहीं जानते कि आज का भारत नरेंद्र मोदी का भारत है जो देश हित को पहले पायदान पर रखता है और किसी के सामने न झुकता है और न किसी से डरता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार विदेश के दौरे कर कई देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं, वह देश आज भारत के साथ लगातार आयात-निर्यात कर रहे हैं. भारत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए इन देशों से संबंध आज काम आ रहे हैं.

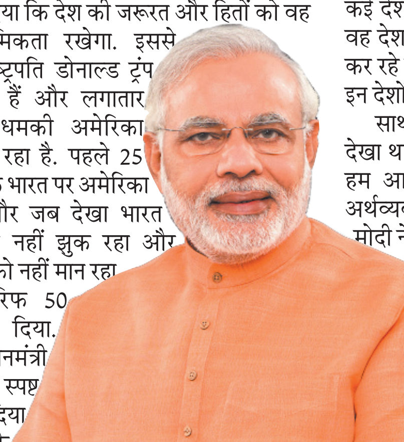

साथ ही मेक इन इंडिया का जो सपना नरेंद्र मोदी ने देखा था आज वह सच साबित हो रहा है. कई क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं. आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्दी ही देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. देशवासियों को अपने प्रधानमंत्री की हर बात पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जो वादे किए थे वह पूरे हुए हैं. हर देशवासी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व महसूस करता है कि उन्हें देश और देशवासियों को समर्पित एक प्रधानमंत्री मिला है जो हमेशा उनकी चिंता करता है.

अजय मिश्रा

भोलेशंकर पूरनकामी,,,,

शिवशंकर भोलेभंडारी ,
दूर करो मन, बरबादी ,

अज्ञान,कुसंग उपजे क्लेश,
दो रामराह,कंटक न शेष ,

श्रद्धा ज्ञान, मन भर दो ,
करो कृपा,भक्ति दृढ़ कर दो ,

रामभक्त त्रिलोक में न अपर ,
करजोर विनय,मेरी राह कर ,

कलजुग,सनातनी मांग रहा,
संग्राम, म्लेच्छ सम्मुखआ रहा,

सनातनी हाथों में अस्त्र गहा,
कर दया दयालु औढरदानी ,
हैं भाव भोलेशंकर,पूरनकामी ,

पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे डॉ. आम्बेडकर

प्रो. विवेकानंद तिवारी

भारत का विभाजन एक चुभता हुआ प्रश्न रहा है. आज भी इसे लेकर सवाल होता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी. भारत और पाकिस्तान की भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाजों में बहुत सारी समानताएं मिलती हैं. इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम के प्रश्न के चलते देश का बंटवारा होने की एक टीस आज भी भारतीयों के मन में है.

डॉ. अंबेडकर ने एक बार कांग्रेस पार्टी की तुलना धर्मशाला से की थी, जहां विभिन्न विचारधारा और विचारधारा वाले लोगों ने शरण ली थे. उन्होंने कहा कि पार्टी में सनातनवादी, विद्वान, समाजवादी, कम्युनिस्ट, रूढ़िवादी और रूढ़िवादी विरोधी विचारक और विरोधाभासी विचारधारा वाले कई अन्य लोग थे. उन्होंने एक ही राजनीतिक इकाई के भीतर ऐसी समानता, विरोधी अलगाव के सह-अस्तित्व के सामान्य उद्देश्य पर प्रश्न उठाया.

मोहम्मद अली जिन्ना को इस विभाजन का सबसे बड़ा कारक माना जाता है तो वहीं सांप्रदायिकता का ज्वार भी इसकी वजह बना. लेकिन कई ऐसे नेता भी उस दौर में थे, जिन्होंने देश के बंटवारे का विरोध किया था. इनमें से ही एक लीडर थे, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर. उनकी पहचान भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर है, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिक मसलों और भारत विभाजन पर भी खुलकर कहा था.

बाबासाहेब आंबेडकर की पुस्तक %पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन% से हम बंटवारे के संदर्भ में उनके विचारों को जान सकते हैं. आंबेडकर ने साफ कहा था कि जब कनाडा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में अलग-अलग संस्कृतियों और पहचान वाले लोग हैं और वे एक साथ रह सकते हैं तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता.

बाबासाहेब आंबेडकर की पुस्तक %पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन% से हम बंटवारे के संदर्भ में उनके विचारों को जान सकते हैं. आंबेडकर ने साफ कहा था कि जब कनाडा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में अलग-अलग संस्कृतियों और पहचान वाले लोग हैं और वे एक साथ रह सकते हैं तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता. हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग-अलग राष्ट्र बताए जाने के सवाल पर भी उन्होंने खुलकर कहा था कि भले ही ऐसा हो, लेकिन साथ रहा जा सकता है.

भीमराव आंबेडकर लिखते हैं, 'इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदू और मुसलमान के अनेक ढंग, तौर-तरीके, धार्मिक तथा सामाजिक रिवाज समान हैं. इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे भी रीति-रिवाज और संस्कार हैं, जो धर्म पर आधारित हैं और वे अलग-अलग हैं. उनके चलते हिंदू और मुसलमान दोनों भागों में विभक्त हैं. प्रश्न यह है कि किस बात पर अधिक बल दिया जाए. यदि उन बातों पर बल दिया जाए, जो दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं तो फिर भारत में दो राष्ट्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती. पर उन बातों पर ध्यान दिया जाता है, जो सामान्य रूप से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में निसंदेह दो राष्ट्रों का सवाल सही है.

इसके आगे वह कनाडा का उदाहरण देते हुए लिखते हैं, %यदि यह मान लिया जाए कि भारत के मुसलमान एक राष्ट्र हैं तो क्या भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जहां दो राष्ट्रों का अभ्युदय होने वाला है? कनाडा के विषय में क्या विचार है? हर कोई जानता है कि कनाडा में अंग्रेज और फ्रेंच दो राष्ट्र हैं. क्या दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज और डच दो राष्ट्र नहीं हैं? कौन नहीं जानता कि स्विटजरलैंड में जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन ये तीन राष्ट्र हैं. क्या कनाडा में फ्रेंचों ने विभाजन की मांग की?% भीमराव आंबेडकर ने उस दौरान उठी विभाजन की लहर और सांप्रदायिक राजनीति का तीखा विरोध किया था. उन्होंने इन देशों का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब ये साथ रह सकते हैं तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता.

कनाडा, स्विटजरलैंड की तरह क्यों नहीं रह सकते एक- आंबेडकर ने लिखा था, कनाडा में फ्रेंच, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों और स्विट्जरलैंड में फेंच और इटालियन्स के उदाहरण के बाद यह प्रश्न उठता है कि भारत में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह मानते हुए हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्रों में विभाजित हैं, वे एक देश में एक संविधान के अंतर्गत क्यों नहीं रह सकते. दो राष्ट्र सिद्धांत के चलते भारत के विभाजन की आवश्यकता ही क्या है. हिंदुओं के साथ रहने पर मुसलमान अपनी राष्ट्रीयता तथा संस्कृति के क्षीण होने को लेकर इतने भयभीत क्यों हैं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का इस्लामी कट्टरवाद के बारे में दृष्टिकोण हमेशा एकदम स्पष्ट था. 18 जनवरी, 1929 के 'बहिष्कृत भारत' के संपादकीय में डॉ. बाबासाहेब ने लिखा, 'मुस्लिम लोगों का झुकाव मुस्लिम संस्कृति के राष्ट्रों की तरफ रहना स्वाभाविक है. लेकिन यह झुकाव हद से ज्यादा बढ़ गया है. मुस्लिम संस्कृति का प्रसार कर मुस्लिम राष्ट्रों का संघ बनाना और जितना हो सके, काफिर देशों पर उनका अलम चलाना, यही उनका लक्ष्य बन गया है. इसी सोच के कारण उनके पैर हिन्दुस्थान में होकर भी उनकी आंखें तुर्कस्तान अथवा अफगानिस्तान की ओर लगी हैं. हिन्दुस्थान मेरा देश है, ऐसा जिनको अभिमान नहीं है और अपने निकटवर्ती हिन्दू बंधुओं के बारे में जिनकी बिल्कुल भी आत्मीयता नहीं है, ऐसे मुसलमान लोग मुसलमानी आक्रमण से हिन्दुस्थान की सुरक्षा करने हेतु सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा मानना खतरनाक है.'

डा बाबा साहब दूरदर्शी थे उन्होंने 1947 में देश विभाजन की विभीषिका को देखा था .वे इस्लाम की फिलास्फी समझ गये थे इसलिए बाबा साहब ने कहा किजब तक भारत से एक भी एक मुस्लिम पाक नहीं जाता तब तक विभाजन बेइमानी होगा.यदि एक भी मुस्लिम भारत में रह गया तो फिर मुस्लिम समस्या देश में खडी हो जायेगी.गांधी जी ,नेहरू जी ने बाबा साहब के तथ्य को नहीं माना और देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है.जो देश के विकास में दीवार बनकर खडा है.